रेलवे में घूसखोरी और कमीशन की अदायगी

1899. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में घूसखोरी तथा कमीशन की अदायगी से संबंधित मामले हाल में सरकार के ध्यान में लाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो घूसखोरी और कमीशन में लिप्त पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भ्रष्टाचार उन्मूलन एक सतत प्रक्रिया है और सरकार रेलों से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए कृत संकल्प है जिसके लिए सतर्कता कार्यकलाप विशेष तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए हैं :—

(i) बुकिंग, आरक्षण, सामान/पार्सल माल और खानपान जैसे जनता से व्यापक संपर्क वाले क्षेत्रों में जहां जनता को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। परेशान किया जा सकता है ।

(ii) जहां भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग।बरबादी होने अथवा राजस्व की चोरी होने की संभावना हो ।

(iii) कर्मचारियों की भर्ती और प्रवरण ।

इन कार्यकलापों में निवारक और दण्डात्मक दोनों ही उपाय शामिल हैं। निवारक उपायों में कदाचारों की रोकथाम अथवा उन्हें कम करने के लिए नियमों प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उनमें आशोधन करना, सूचना इकट्ठी करना, निगरानी रखने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों और भ्रष्टाचार बहुल क्षेत्रों की पहचान करना, संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानांतरण करना आदि शामिल हैं। दण्डात्मक उपायों के रूप में रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाये गये कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदा नियमों के अनुसार कड़े दण्ड दिए जाते हैं ताकि अन्य व्यक्ति ऐसा न कर सकें।

प्रलोभन जांच के परिणामस्वरूप और 1991 के दौरान शिकायतों की जांच करने के परिणामस्वरूप 2740 रेल पदाधिकारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति (बर्खास्तगी, सेवा से हटाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और पदावनति आदि) की कार्रवाई की गई थी और 8130 व्यक्तियों के विरुद्ध छोटी शास्ति की कार्रवाई की गई थी। 1991 के दौरान 898 पदाधिकारियों को बड़ी शास्ति का दंण्ड दिया गया और 7383 पदाधिकारियों की छोटी शास्ति का दण्ड दिया गया।

परिवर्तन की एक-आमान प्रणाली

1400. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के मामले में एक आमान की प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश इस प्रकार के परिवर्तन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में शुरू किये जाने वाले शेष परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली निम्नलिखित लाइनों को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए बनाई गई

कार्य योजना के चरण–I में शामिल कर लिया गया है :–

(1) बुढ़वल–सीतापुर
(2) इलाहाबाद सिटी–वाराणसी
(3) मेडिहार–बलिया
(4) बलिया–छपरा जं०
(5) लालकुआं–काशीपुर
(6) मनकापुर–कटरा
(7) कटरा–फैजाबाद (सरयू पर पेन पुल सहित
(8) कानपुर–कासगंज
(9) नरकटियागंज–गोरखपुर
(10) मऊ–शाहगंज

(ङ) दूसरे चरण में शुरू किए जाने वाले आमान परिवर्तनों की सूची चरण–I के अंत में बनाई जाएगी।

Linking Chandigarh with Ludhiana by Rail

1401. SHRI JAGIR SINGH DARD: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government consideration to link Chandigarh with Ludhiana by rail; and

(b) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) A survey has been ordered for a new line between Chandigarh and Rajpura which will provide a direct link between Ludhiana and Chandigarh. Further action will depend on the results of the servey and availability of resources in the coming years.

जबलपुर और दिल्ली के बीच सीधी द्रुतगामी रेल गाड़ी

1402. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के जबलपुर शहर और दिल्ली को महाकौशल एक्सप्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य सीधी द्रुतगामी रेल गाड़ी से जोड़ने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाईयां आ रही हैं ;

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली जबलपुर रेल सेवा घाटे में चल रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लाइन क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं की कमी ।

(ख) क्षमता बढ़ाने और टर्मिनल सुविधाओं की विकास की योजना तैयार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

Railway Users' Consultative Committees

1403. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of meetings of the Suburban Railway Users' Consultative Committee, Central Railway, Bombay; Suburban Railway Users' Consultative Committee, Western Railway, Bombay; Divisional Railway Users' Consultative Committee, Bombay Division, Central Railway, and Divisional Railway Users' Consultative Committe, Bombay Division, Western Railway, held since 1985;

(b) whether it is a fact that in each of the above meetings, the Members have action has been taken, and those on which

(c) if so, the issues on which follow-up action has been taken, and those on which follow-up action has not been taken;

(d) the reasons for not taking follow-up action thereon; and

(e) what steps Government propose to take to make the working of these Consultative Committees more effective?